(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में छावनी बोर्ड

1891. **श्री ओंकार सिंह लखावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में कितने छावनी बोर्ड कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या अजमेर में छावनी बोर्ड का एक वार्ड पलटन बाजार में है, यदि हां, तो उस क्षेत्र में पानी, सफाई, स्वास्थ्य तथा नागरिक सुविधाओं का व्यवस्था संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) अजमेर के छावनी क्षेत्र में नागरिकों द्वारा निर्माण संबंधी पूर्व अनुमति लिये बिना दशकों पहले बनाये गये मकानों को विनियमित करने के लिऐ क्या कार्रवाई की जा रही है?

रक्षा मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज : (क) राजस्थान मे अजमेर और नसीराबाद में दो छावनी बोर्ड कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी, हां। अजमेर छावनी के पलटन बाजार वार्ड में प्रतिदिन एक लाख लीटर पानी प्राप्त होता है और उसका 16 नलों तथा 180 निजी कनेक्शनों के माध्यम से एक घंटे के लिये वितरण किया जाता है। सोडियम लैम्प/टयूब लाइट लगे 57 खंभों के माध्यम से सड़कों पर बिजली उपलब्ध कराई जाती है। पक्की सड़कों, सार्वजनिक शौचालयों, टाइल्सयक्त नालियों की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर सीमेंट के कूडाघरों का निर्माण करवाया गया है। इस क्षेत्र में छावनी बोर्ड एक औवद्यालय भी चला रहा है।

(ग) प्रत्येक मामले पर गुण-दोष के अनुसार कार्रवाई की जाती है और छावनी बोर्ड द्वारा छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 178 से 185 में समविष्ट प्रावधानों के अनुसार समुचित निर्णय लिया जाता है।

System of integrated direction and command

1892. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to bring about a change in the decision-making process of the armed forces by introducing the system of integrated direction and command; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI GEORGE FERNANDES):
(a) and (b) The process of refining and improving the higher comm and organisation and structure in the armed forces is a matter that engages the attention of the Gov ernment including senior officials of the armed forces on a continu ing basis with a view to evolving a structure that is suited to the specific requirements of India. This has to take into account the exis ting command organisation and structure, the historical experience of the country and the specific requirements of contemporary forms of warfare. Recently Gov ernment has set up a National Security Council of which the stra tegic Policy Group, which inclcudes the Chiefs of staff of three Services,is a constituent unit. One of the prio rity tasks of this body would be to undertake a strategic defence review. The Defence Minister's Committee which meets every month and Raksha Mantri's weekly meeting are also forums where such matter are discussed from time to time.